भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *62
दिनांक 07 फरवरी, 2023 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार के अवसर

***62 श्री धनुष एम. कुमार:**
श्री जी सेल्वम:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र देश में प्रमुख रोजगार सघन उद्योगों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तमिलनाडु में सृजित रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक जनशक्ति की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) और मेगा फूड पार्कों (एमएफपी) के संचालन के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास हेतु देश में रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों और केंद्रों का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए तमिलनाडु में कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है; और

(ड.) उक्त अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और मेगा फूड पार्कों की स्थापना करने तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की मौजूदा क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री पशुपति कुमार पारस)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार के अवसर के बारे दिनांक 07 फरवरी, 2023 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *62 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) और (ख): जी, हां। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में लगे कुल व्यक्तियों का 12.2% योगदान है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	लगे हुए व्यक्तियों की संख्या
2017-18	2,26,675
2018-19	1,97,080
2019-20	2,06,293

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2017-18,2018-19 और 2019-20, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने मैसर्स फीडबैक बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के माध्यम से "2021-2030 के दौरान भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मानव संसाधन और कौशल आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए अध्ययन" शीर्षक से एक अध्ययन शुरू किया था। 2022 में प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, 2021-30 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता की संख्या लगभग 13.4 लाख व्यक्ति है।

(घ): कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएम कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षित/प्रबोधित किए उम्मीदवारों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	प्रशिक्षित / प्रबोधित
2019-20	83,658
2020-21	65,621
2021-22	7,022
2022-23 (31.12.2022 तक)	727
कुल	**1,57,028**

इसमें से 2129 उम्मीदवारों को पीएमकेवीवाई के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में प्रशिक्षित/ प्रबोधित किया गया है।

एमओएफ़पीआई कोई कौशल विकास योजना कार्यान्वित नहीं कर रहा है। प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएम-एफएमई) योजना के छमता निर्माण घटक में योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और प्रारम्भिक पूंजी का लाभ उठाने वाले पीएमएफएमई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों (व्यक्तियों/स्व-सहायता समूहों/किसान उत्पादक संगठनों/सहकारिताओं) को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। तमिलनाडु में 28 मास्टर ट्रेनरों, 15 जिला स्तरीय प्रशिक्षकों और 71 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ड.): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन/अनुदान निम्नानुसार हैं:

योजना का नाम	**प्रदान किए गए प्रोत्साहन/ जारी किए गए अनुदान (करोड़ रुपये)**
प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)	3405.74
प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएम-एफएमई) योजना	829.45
उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस)	107.32
कुल जारी किया गया	**4342.51**

******